उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विज्ञापन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

सच का साथी.....

बी पी एस न्यूज

www.bpsnews.in

वर्षः 11 || अंकः1 || पृष्ठः 8 || मूल्य 2:00/- रुपए || कानपुर || सोमवार || 02 फरवरी-2026

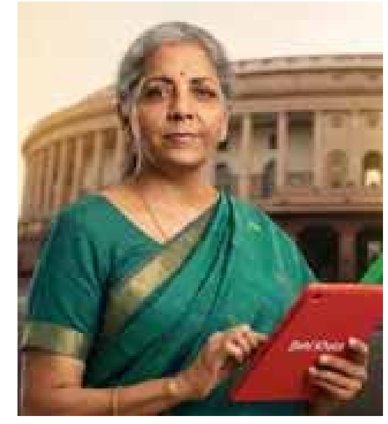

अंदर के पृष्ठ पर | जनगणना 2027 की तैयारी तेज, कानपुर में 13 हजार से अधिक कार्मिक होंगे तैनात 8 | भाजपा ने अनादि काल से तोड़ी है सनातनी परंपरा : अखिलेश 5

बजट में सबका साथ-सबका विकास पर दिया जोर : सीतारमण

» बजट 2026 से अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश- वित्त मंत्री

» बीपीएस न्यूज

नई दिल्ली। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने आम आदमी से लेकर गरीब और किसानों के लिए कई घोषणाएं की। लेकिन, मीडिल क्लास को इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी।उन्होंने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब पहले की तरह ही रहेंगे। इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, शेयर बाजार को भी कोई राहत नहीं मिलने से मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई है और निफ्टी50 पौने तीन फीसदी गिरकर 25600 के नीचे चला गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जांएगे, जो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी के बीच तैयार होंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर, एडवांस्ड फाइबर, नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद दी जाएगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। हम सुधार गतिविधियों को जारी रख रहे हैं। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त वातावरण तैयार करना है। 21वीं सदी पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रौद्योगिकी का लाभ आम आदमी को मिले।

बजट में सरकारी कैपेक्स को बढ़ाने पर जोर- वित्त मंत्री

ऐतिहासिक बजट के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण को धन्यवाद- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ÷विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने विकसित

भारत की रूपरेखा को और स्पष्ट करते हुए आज केंद्रीय बजट पेश किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बजट दिशा-निर्देशों के मार्गदर्शन और देखरेख के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इस बजट को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह बजट देश के 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को दर्शाता है। यह विकसित भारत के दृष्टिकोण और मिशन का प्रतीक है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट 2026 को बताया ऐतिहासिक

बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ÷यह एक ऐतिहासिक बजट रहा है... पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी में 7.5त्न की वृद्धि हुई है, महंगाई नियंत्रण में रही है, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण है, और कृषि, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि हुई है।÷

यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भर के लिए- रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

केंद्रीय बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ÷यह बजट जनता की भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। इसके अलावा, यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत के विजन को मजबूत आधार प्रदान करता है। वहीं, इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं... ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद, इस बजट ने देश की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के हमारे संकल्प को बल दिया है। इस वर्ष, हमारे सशस्त्र बलों के कुल पूंजीगत व्यय के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और इस बजट का मुख्य फोकस हमारे तीनों सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर है। इसके लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है... संक्षेप में, यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन को मजबूत करता है।

1 अप्रैल से बदलेगा आयकर कानून, आपकी कमाई व बचत पर क्या होगा असर

आम करदाताओं और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने विदेश यात्रा और शिक्षा को किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को 5 से 20 प्रतिशत के स्लैब से घटाकर सीधे 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। यही राहत लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत शिक्षा और चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी दी गई है, जहाँ अब टीसीएस की दर 2 प्रतिशत होगी। इसके अलावा, टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को लचीला बनाते हुए %रिवाइज्ड रिटर्न% दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि व्यापक समीक्षा के बाद तैयार किया गया %आयकर अधिनियम 2025% आगामी 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव में आएगा।

जो भारी माहौल बनाया, वो पूरी तरह फीका, कांग्रेस-सपा का तंज

» बीपीएस न्यूज

नई दिल्ली । लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (01 फरवरी) को बजट 2026 पेश किया। वित्त मंत्री ने करीब 85 मिनट का बजट भाषण दिया। किसान, रेलवे, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणा की गई। हालांकि इस बार आम आदमी के लिए कोई बड़ा एलान नहीं हुआ।

कांग्रेस का सरकार पर तंज, बजट बताया फीका

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से फीका बजट करार दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि %हालांकि दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन किया जाना अभी बाकी है, लेकिन 90 मिनट बाद ही यह स्पष्ट हो गया है कि बजट 2026/27 के बारे में जो भारी माहौल बनाया गया था, उसके मुकाबले यह कहीं कमतर रहा है। यह पूरी तरह फीका साबित हुआ।÷

राहुल गांधी ने नहीं दिया जवाब

केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कल कहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कल संसद द्वारा दिए गए मंच का इस्तेमाल करके बोलूंगा।

ममता ने रेल कॉरिडोर के ऐलान पर केंद्र को घेरा

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने (वित्त मंत्री)तीन कॉरिडोर के बारे में जो कहा, वह बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। सरासर झूठ। यह पहले से ही प्रोसेस में है और हमने वहां काम शुरू कर दिया है। पुरुलिया में जंगलमहल जंगल सुंदरी प्रोजेक्ट में, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 72,000 करोड़ रुपये का निवेश होने वाला है। उन्होंने बंगाल को एक पैसा भी नहीं दिया है। सिर्फ एक टैक्स है, त्रस्ज्ञ। वे हमारा पैसा ले रहे हैं और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि वे हमें पैसा दे रहे हैं। यह हमारा पैसा है। इसलिए, उनके पास सरकार चलाने और इस तरह देश को खत्म करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वे देश के आर्थिक ढांचे, इस देश के संवैधानिक ढांचे, स्वतंत्र एजेंसियों को खत्म करना चाहते हैं। वे बातें ज्यादा करते हैं लेकिन काम कम करते हैं।

अखिलेश ने बताया 5 फीसदी आबादी वाला बजट

समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि यह बजट गरीबों और गांवों में रहने वालों की समझ से परे है। इस बजट में न तो नौकरी दी गई है और न ही रोजगार के अवसर। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकती है। नौकरी रोजगार दिए नहीं। सपने

कैंसर की दवाएं और विदेश यात्रा सस्ती, शराब और लग्जरी घड़ियाँ हुई महंगी

» बीपीएस न्यूज

नयी दिल्ली। अपना रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कस्टम ड्यूटी में बड़े बदलाव किए, जिसका असर पूरे भारत में कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज़ दोनों पर पड़ेगा। 17 कैंसर की दवाओं और सात दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर टैक्स माफ होगा, जिससे वे सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा, माइक्रोवेव ओवन, एयरक्राफ्ट पार्ट्स और विदेशी टूर पैकेज भी सस्ते होंगे, क्योंकि सरकार ने विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर झ्रष्ट्स दर कम कर दी है। हालांकि, दूसरी ओर, घड़ियों और शराब सहित लग्जरी सामान पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, जिससे वे महंगे हो जाएंगे।

जैसा कि उम्मीद थी, बजट में कोई बड़ी घोषणा या पर्सनल टैक्स में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि सीतारमण ने फिस्कल कंसोलिडेशन रोडमैप का पालन किया और क्रॉस-सेक्टर सुधारों की घोषणा की। एक बड़ी घोषणा स्त्रङ्क्व 2026-27 के लिए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करना था, जो पिछले साल अलॉट किए गए 11.2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है।

हुआ सस्ता-कैंसर की दवाएं- सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 महत्वपूर्ण दवाओं पर बेसिक सीमा शुल्क को पूरी तरह हटा दिया है। इससे कैंसर का इलाज काफी सस्ता होने की उम्मीद है।

दुर्लभ बीमारियों का इलाज- सात दुर्लभ बीमारियों के लिए आयात की जाने वाली दवाओं और विशेष चिकित्सा भोजन पर भी शुल्क की छूट दी गई है।

विदेश यात्रा विदेश घूमने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ओवरसीज टूर पैकेज पर लगने वाले जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से घटाकर अब मात्र 2 प्रतिशत कर दिया गया है।किचन अप्लायंसेज - माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास पुर्जों पर सीमा शुल्क कम किया गया है, जिससे माइक्रोवेव की कीमतों में गिरावट आएगी।

लेदर और फुटवियर- चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जूते-चप्पल और चमड़े के सामान के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दी है।

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स- मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरियों पर शुल्क कटौती जारी रहने से ये गैजेट्स आपके लिए किफायती बने रहेंगे।

बाहर से निजी इस्तेमाल के सामान मंगाना हुआ सस्ता

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश बजट में लोगों को एक बड़ी राहत दी है. यह राहत निजी उपयोग के लिए आयातित सामानों पर है. उन्होंने सभी ड्यूटीएबल सामान पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) को 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने का ऐलान किया. मतलब अब इन सामानों पर सीमा शुल्क आधा हो गया है. 50 फीसदी की यह कटौती कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को रेशनलाइज

क्या महंगा हुआ

» घड़ियों और शराब सहित लग्जरी सामान महंगा होने वाला है।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य दोतरफा है-सामाजिक कल्याण- जीवन रक्षक दवाओं को आम आदमी की पहुँच में लाना।

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग- कच्चे माल पर ड्यूटी घटाकर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और तैयार माल जैसे लग्जरी घड़ियाँ पर ड्यूटी

बजट 2026 पर भाजपा-कांग्रेस आमने सामने: वैष्णव ने गिनाई बड़ी घोषणाएं

» एआई अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा परमाणु ऊर्जा : अश्विनी वैष्णव

» पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने दिखाया आईना

» बीपीएस न्यूज

नई दिल्ली । केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बजट पेश होने के तुरंत बाद भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गईं। जहां एक ओर सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट को विकासोन्मुख और भविष्य की नींव रखने वाला बताया, वहीं कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बजट को आर्थिक रणनीति और नेतृत्व दोनों के स्तर पर विफल करार दिया।

आर्थिक रणनीति में फेल बजट- चिदंबरम का तीखा हमला

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बजट भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा हमारा निष्कर्ष साफ है यह बजट आर्थिक रणनीति और इकोनॉमिक स्टेट्समैनशिप की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने योजनाओं, कार्यक्रमों, मिशनों, फंड और समितियों की संख्या बढ़ाने पर ही जोर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि इनमें से कितनी योजनाएं अगले

साल तक भुला दी जाएंगी।

आयकर बदलाव पर भी उठाए सवाल

चिदंबरम ने कहा कि आयकर अधिनियम 2026, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होना है, उसके पारित होने के कुछ महीनों बाद ही दरों में बदलाव कर दिए गए।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश की अधिकांश आबादी आयकर के दायरे में ही नहीं आती, इसलिए इन बदलावों का आम जनता पर सीमित असर होगा।

अप्रत्यक्ष करों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए बजट भाषण के सिर्फ कुछ ही पैराग्राफ मायने रखते हैं और उनमें दी गई रियायतें भी बेहद मामूली हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण की अनदेखी का आरोप

पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार पर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा या तो सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा ही नहीं या फिर जानबूझकर उसे पूरी तरह दरकिनार कर दिया। चिदंबरम ने अमेरिका द्वारा लगाए गए दंडात्मक टैरिफ, चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे, स्त्रष्ठ्ठ को लेकर अनिश्चितता और लगातार हो रहे स्त्रक्व्र आउटफ्लो जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र किया और कहा कि बजट भाषण में इनका कोई ठोस समाधान नहीं दिखा।

चिदंबरम ने यहां तक कहा कि बजट भाषण के दौरान तालियां भी औपचारिक थीं और कई लोग जल्दी ही रुचि खो बैठे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संसद टीवी का प्रसारण भी कुछ समय के लिए बंद हो गया।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की बुनियादी ढांचा और ऊर्जा नीति को लेकर दो अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत करने जा रही है, जो पश्चिम बंगाल को गुजरात से जोड़ेगा। मंत्री ने कहा कि पश्चिमी और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर में अब तक उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी है और ये लगभग अपनी क्षमता सीमा तक पहुंच चुके हैं। इन दोनों कॉरिडोर पर फिलहाल प्रतिदिन करीब 400 मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं। इसी बढ़ते दबाव को देखते हुए नए फ्रेट कॉरिडोर की आवश्यकता महसूस की गई है, जिससे लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।

ऊर्जा और तकनीक के संबंध पर बात करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि परमाणु ऊर्जा भविष्य की एआई आधारित अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई संरचना की पांचवीं परत यानी ऊर्जा लेयर में परमाणु ऊर्जा की अहम भूमिका होगी। मंत्री के अनुसार, एआई आधारित सिस्टम को लंबे समय तक स्थिर और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे परमाणु ऊर्जा बेहतर तरीके से उपलब्ध करा सकती है। यह न केवल क्लीन एनर्जी प्रदान करती है, बल्कि एआई इकोनॉमी की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगी।

सात नए हाई-स्पीड कॉरिडोर से बदलेगा देश का परिवहन परिदृश्य- अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में किए गए सुधारों का असर साफ दिखाई दे रहा है और दुर्घटनाओं में करीब 95 प्रतिशत तक कमी आई है। उन्होंने बताया कि अब सरकार सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रखरखाव पर विशेष जोर दे रही है। मंत्री के अनुसार, ट्रैक मेंटेनेंस, लोको, वैगन और कोच की नियमित देखभाल, सुरक्षा कवच प्रणाली (कवच) का तेजी से विस्तार, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (ह्व॥श्व) सिस्टम का उन्नयन और नए स्टेशनों का निर्माण इन सभी कदमों से रेलवे की सुरक्षा और बेहतर होगी।

संत रविदास जयंती पर निकली शोभायात्रा के दौरान खूनी संघर्ष

» बीपीएस न्यूज

रुड़की। रुड़की में संत रविदास जयंती पर निकली शोभायात्रा के दौरान रविवार को खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान फायरिंग और पथराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, कई लोग घायल हुए हैं।तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

जानकारी के अनुसार, भगवानपुर थाना क्षेत्र के बीनारसी गांव में शोभायात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि खूनी संघर्ष में बदल गया। अचानक दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई और पथराव भी हुआ। इस दौरान आनंद(28)निवासी ग्राम बिनारसी की मौत हो गई। वहीं, विशाल(25) और योगेंद्र(27) को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उधर, ग्रामीण शव को नहीं उठाने दे रहे हैं।

बी पी एस न्यूज परिवार की ओर से सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

संपादक
(बी.पी.साहू)
मो-8423454502,
व्हाटसअप-9335908846

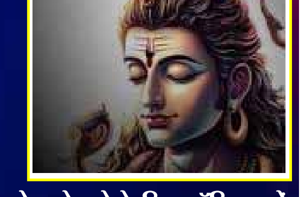

बी पी एस न्यूज लेटेस्ट खबरें पढ़ने व देखने के लिए लॉगिन करें
www.bpsnews.in

अपनी बात....
संपादकीय ....

महाराष्ट्र में खलेगी अजित पवार की कमी

बुधवार सुबह बारामती के पास हुई एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार व चालक दल के सदस्यों समेत पांच लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। मुंबई से बारामती आ रहा चार्टर विमान मौसम की खराबी के कारण रनवे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों का असली पता जांच के बाद ही चलेगा, मगर प्रथम दृष्टया धुंध के कारण दृश्यता में कमी ही बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में छह बार उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार के राज्य में राजनीतिक योगदान को नकारा नहीं जा सकता। राज्य में तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य विपक्षी दलों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। हालांकि, ममता बनर्जी ने उनकी मौत को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु व चाचा शरद पवार ने उनकी मृत्यु को लेकर राजनीतिक बयानबाजी को खारिज किया है। निश्चय ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजित पवार की असामयिक दुर्घटना में मृत्य ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य जरूर पैदा कर दिया है। वहीं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के मुताबिक दुर्घटना क्रैश लैंडिंग के दौरान हुई। रनवे के निकट हुए हादसे में विमान में आग लग गई और स्थानीय लोगों के प्रयासों के बावजूद किसी को बचाया नहीं जा सका। विमान लियरजेट-45 सोलह साल पुराना था। घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। निस्संदेह, अजित पवार जनता के नेता थे और जमीनी स्तर पर लोगों से उनका गहरा जुड़ाव था। बताया जाता है कि प्रशासनिक मामलों में उनकी समझ गहरी थी। वे वंचित वर्ग को सशक्त करने के प्रयासों के लिये जाने जाते रहे हैं।बहरहाल, अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में उनके बदलते दांव-पेचों के लिये याद किया जाता रहेगा। उनके बारे में कहा जाता रहा है कि वे उस कहावत को हकीकत बनाते रहे हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही स्थायी दुश्मन। वे अपनों के साथ तो रहे, गैरों को भी रास आए। उन्होंने चाचा और अपने राजनीतिक गुरु शरद पवार से राजनीति के गुर सीखे। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता रहा है, लेकिन अजित पवार ने उनसे अलग होकर अपनी नई राह भी बनायी। यूं तो उन्होंने चाचा शरद के साथ राजनीतिक पारी शुरू की लेकिन साल 2023 आने तक वे एकला चलो की राजनीति करने लगे। हालांकि, उन्होंने चाचा शरद पवार की छत्रछाया में राजनीति का ककहरा सीखा लेकिन एक समय वे पार्टी का सिंबल भी ले जाने में कामयाब रहे। फिर शरद पवार को नई पार्टी बनाकर उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी। बारहवीं तक पढ़ाई के बावजूद वे अनुभवी नीतिकारों की सहायता से एक बेहतर प्रशासक भी साबित हुए। सहकारी चीनी मिलों से राजनीति की शुरुआत करने वाले पवार विधायक से लेकर सांसद तक चुने जाते रहे। वे राज्य में छह बार उप मुख्यमंत्री बने। साल 1991 में पहली बार बारामती से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने, लेकिन चाचा शरद पवार के लिये बाद में सीट खाली भी की। वे सबसे पहले 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। उनकी लोकप्रियता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वे सात बार विधायक चुने गए। फिर वे विलासराव देशमुख की कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार में पहली बार सिंचाई मंत्री बने। फिर ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। बाद में वे एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन में जल संसाधन मंत्री भी रहे। साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उनके अचानक भाजपा गठबंधन के साथ आने और उप मुख्यमंत्री बनने ने सबको चौंकाया था। फिर पवार साल 2023 में महायुति गठबंधन का हिस्सा बनकर पांचवीं बार उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि, एनसीपी में विभाजन के बाद शरद पवार परिवार से संबंध बनाये रखे। इसके बावजूद कि उन्होंने एनसीपी का नाम और सिंबल तक ले लिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार को कई मायनों में हमेशा याद किया जाएगा।

एफटीए से यूरोप-भारत व्यापार को बूस्टर डोज़

संजय द्विवेदी

अब देखना होगा कि यह बहु-प्रतीक्षित समझौता भारत के 140 करोड़ और यूरोपीय संघ के 45 करोड़ लोगों हेतु कितना बड़ा अवसर लाता है। इंतज़ार रहेगा कि एफटीए का ईयू-अमेरिका व भारत-चीन के उभयपक्षीय संबंधों पर क्या असर पड़ता है।बिना एफटीए के भी यूं तो यूरोपीय देशों से भारत का व्यापार दशकों से होता आ रहा है। लेकिन, ऐसा माना गया कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने से इसे बूस्टर डोज़ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए कहा, 'ईयू-इंडिया एफटीए सभी सौदों की जननी है। यह सौदा यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों का पूरक है। भारत में कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा और जूट जैसे विभिन्न क्षेत्रों को इस व्यापार समझौते से फायदा होने वाला है।' पीएम मोदी ने कहा कि यह डील भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करेगी, और सर्विस सेक्टर को नया सहारा देगी।

वर्ष 2007 में शुरू हुई वार्ता प्रक्रिया का समापन देर-सवेर हुआ ही। मनमोहन सिंह से आरम्भ वार्ता को मोदी ने अंजाम दिया। यहां तक पहुंचने में 19 साल लगे। लेकिन रुकिए, अभी बहुत कुछ होना बाक़ी है। सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की भाषाओं में एफटीए के कानूनी दस्तावेज़ों को प्रकाशित करना होगा। सभी धाराओं की एक-एक करके जांच होगी, जिसे 'लीगल स्क्रबिंग' कहते हैं, यूरोपीय परिषद द्वारा औपचारिक मंज़ूरी के बाद, यूरोपीय संसद की सहमति चाहिए, इसके प्रकारांतर भारतीय कैबिनेट द्वारा पुष्टि होगी। इन सबसे गुज़रने के बाद, 2027 तक इसके लागू होने की उम्मीद है।

मंगलवार को यूरोपियन कमीशन की प्रतिक्रिया ग़ौर करने लायक है– 'इस डील से ईयू कंपनियों और किसानों को ज़्यादा निर्यात करने में मदद मिलेगी। इस डील से पहले ही आठ लाख यूरोपीय नौकरियों को सपोर्ट मिलता रहा है। अब एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से, और भी ज़्यादा यूरोपीय नौकरियां मिल सकती हैं।' यूरोपियन कमीशन का सन्देश था, 'उम्मीद है कि यह समझौता भारत को होने वाले ईयू एक्सपोर्ट को दोगुना कर देगा। इसके अलावा, भारतीय सर्विस मार्केट तक बेहतर पहुंच, खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज़, मैरीटाइम सर्विसेज़ और दूसरे मुख्य सेक्टर्स में, नए बिज़नेस और रोज़गार के अवसर पैदा करेगी।'

यूरोपीय आयोग ने जानकारी दी, कि इस डील से 90 फीसद से ज़्यादा यूरोपीय संघ के देशों के सामानों के एक्सपोर्ट टैरिफ खत्म, या कम कर दिया जाएगा। इससे यूरोपीय प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी में हर साल अरबों यूरो तक की बचत होगी। यूरोपियन कमीशन ने कहा, 'भारत ने किसी भी व्यापारिक सहकार को इतनी बड़ी ट्रेड ओपनिंग नहीं दी है। इससे एक्सपोर्ट को तेज़ और आसान बनाने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को सहज बनाया जायेगा।'

27 जनवरी को डील के तुरंत बाद यूरोपियन कमीशन ने आधिकारिक जानकारी दी कि भारत ईयू को टैरिफ में ऐसी छूट देगा, जो उसके किसी भी दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर को नहीं मिली है, जिससे ईयू एक्सपोर्ट के लिए भारतीय बाजार में पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। उदाहरण के लिए, कारों पर टैरिफ धीरे-धीरे 110 प्रतिशत से घटकर 10 फीसद हो जाएगा, जिसमें हर साल 250,000 गाड़ियों का कोटा होगा। मशीनरी पर 44 प्रतिशत, केमिकल्स पर 22 परसेंट और फार्मास्यूटिकल्स पर 11 प्रतिशत तक के ऊंचे टैरिफ को ज़ीरो पर ले आया जाएगा। टैरिफ एक टैक्स है, जो कोई देश अपने यहां विदेश से आयात होने वाले समान पर लगाता है। इससे विदेश से आने वाला सामान महंगा हो जाता है, और जिस देश में सामान आता है, उसे टैक्स से आय होता है।

यूरोपियन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर एक चार्ट के ज़रिये सारा गणित समझाया है। कमीशन ने वर्ष 2024 को आकलन का आधार बनाया, जिसमें मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण पर 16.3 बिलियन यूरो बतौर टैरिफ देने पड़े थे। एफटीए के कार्यान्वयन के बाद, यूरोपीय संघ के देशों को टैरिफ की देनदारी ज़ीरो प्रतिशत हो जाएगी। विमान और अंतरिक्ष यान निर्यात पर 11 प्रतिशत के हिसाब से 6.4 अरब यूरो टैरिफ के रूप में 2024 में देना पड़ा था, आगे से यह शून्य हो जाएगा। ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण के एक्सपोर्ट पर 27.5 प्रतिशत के हिसाब से 3.4 बिलियन यूरो देना पड़ा था, इनमें से 90 फीसद प्रोडक्ट पर शून्य टैरिफ लगा करेगा। प्लास्टिक पर भी ज़ीरो टैरिफ लगा करेगा, जिससे यूरोपीय संघ के देशों को 2 अरब 20 करोड़ यूरो की बचत होगी। केमिकल्स पर 22 प्रतिशत टैरिफ आगे से शून्य हो जायेगा, उससे 3 अरब 20 करोड़ यूरो की बचत होगी। आयरन एंड स्टील पर भी 22 प्रतिशत से शून्य टैरिफ हो जाने से डेढ़ अरब और फार्मास्युटिकल्स पर टैरिफ शून्य हो जाने के बाद 1 अरब 10 करोड़ का फायदा यूरोपीय संघ के देशों को होना है।

इस डील से यूरोपीय संघ के किसानों की बल्ले-बल्ले होनी है। यूरोपियन कमीशन ने समझाया है, 'यह एग्रीमेंट ईयू से एक्सपोर्ट होने वाले एग्री-फूड प्रोडक्ट्स पर अक्सर लगने वाले बहुत ज़्यादा टैरिफ (औसतन 36 प्रतिशत से ज़्यादा) को हटाएगा या कम करेगा, जिससे यूरोपीय किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार खुल जाएगा। जैसे वाईन पर 150 प्रतिशत टैक्स है, उसे घटाकर प्रीमियम रेंज के वास्ते 20 परसेंट और मीडियम रेंज पर 30 फीसद टैरिफ लाने के वास्ते सहमति बन गई है। स्पिरिट्स पर टैरिफ 150 प्रतिशत से घटाकर 40 पर ले आएंगे। ईयू देशों से भारत भेजे जाने वाले बीयर पर 110 प्रतिशत टैरिफ है, उसे कम कर 50 फीसद कर देना है। जैतून का तेल, मार्जरीन और अन्य वनस्पति तेल पर जो 45 प्रतिशत टैरिफ लगता था, वो ज़ीरो हो जायेगा। कीवी और नाशपाती पर 33 से घटाकर 10 फीसद, फलों के जूस और नॉन-अल्कोहलिक बीयर पर 55 प्रतिशत टैक्स लगा करता था, आगे से ज़ीरो हो जायेगा, प्रोसेस्ड फ़ूड (ब्रेड, पेस्ट्री, बिस्कुट, पास्ता, चॉकलेट, पालतू जानवरों का खाना) पर टैरिफ 50 प्रतिशत से ज़ीरो कर देंगे। भेड़ के मांस पर 33 फीसद टैरिफ लगाते थे, उसे भी ज़ीरो कर देंगे। सॉसेज और मांस से बने अन्य प्रोडक्ट्स पर जो 110 फीसद तक टैरिफ लगते थे, जब एफटीए लागू होगा, उसे 50 प्रतिशत पर ले आया जायेगा।'

निश्चित रूप से इसके लिए चेयरमैन विनीत जोशी तथा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीधे सीधे जिम्मेदार हैं

बड़ा सवाल: क्या न्यायपालिका चाहती है सबको मिलें समान अवसर..!

राजनीतिक विशलेषक एवं पत्रकार जौनपुर यूपी

पंकज सीबी मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद जिसने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को झुलसने से बचा लिया। अमेरिका में 1980 तक गोरों और कालों के लिए अलग अलग शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था थी। तो क्या भारत में भी ऐसा करना चाहता था कोई ? कौन था वह ? समाज तोड़ने के पीछे कौन सा चेहरा या चेहरे हैं , पता लगाइए ? यह जरूरी है। दिग्विजय सिंह क्या बीजेपी के सत्ता में रहते हुए भी इतने बलवान हैं जो वो ये कर सकें अकेले ? यह जानना बहुत जरूरी है कि यह सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की भारी चूक है अथवा इसके पीछे उस लॉबी का षड़यंत्र था जो 12 सालों से सरकार गिराने में हर तरह से नाकामयाब रही है ? देश को 89 इ 90 के मंडल दावानल में कौन झोंकना चाहता था ? किसकी मंशा थी कि जाति जाति खेलने की ? अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी न्यू रेगुलेशन पर रोक लगा दी तो ये मान लें कि क्या न्यायपालिका सच में चाहती है कि सबको समान अवसर मिले और 80 सालों से चला आ रहा सवर्ण अधिकारों के शोषण पर लगाम लगे।

जो लोग यूजीसी रेगुलेशन का समर्थन कर रहे थे वो स्टे के बाद संविधान पर सवाल उठा रहे जबकि रेगुलेशन के विरुद्ध आंदोलन कर रहे लोग क्या मांग रहे हैं ? क्या कोई अधिकार या आरक्षण ? कोई सुविधा या कानून ? नहीं ना। वे चाह रहे हैं कि उन्हें पहले ही अपराधी न मान लिया जाय और उनके विरुद्ध होने वाले अपराध को भी अपराध माना जाय। क्या यह बिल्कुल ही अनैतिक मांग है ? अपनी इस मांग को लेकर मुखर हुआ वर्ग किस दल का पारंपरिक वोटर है ? इनमें से अधिकतर लोग वर्तमान सत्ता पक्ष के समर्थक हैं और चुनावों के समय सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं, तो क्या अपनी ही सरकार से स्वयं को अपराधी घोषित नहीं किए जाने की उम्मीद करना अनैतिक है, जवाब सवाल गलत है ? आप सोशल मीडिया पर कंचना यादव, राजकुमार भाटी इत्यादि के हैंडल देख लीजिये , आज इस आंदोलन के बहाने सवर्णों को गाली देने वाले, उन्हें फसाने की खुली धमकी देने वाले, और हिंदुत्व के खंडित होने की बातें करने वालो पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो पाती।

कौन लोग हैं जो समाज को बाँट रहे ? ये अधिकांश वे है जो विरोधी दल के समर्थक हैं और सदैव ही सत्ता को जातिवाद से , सवर्णों के सनातन होने के कारण और हिंदुत्व की विचारधारा को गाली देते आ रहे हैं। क्या वे इस रेगुलेशन के लागू हो जाने से सत्ता के समर्थक हो जाते ? नहीं न ! फिर आप उनसे सहमत कैसे हो पा रहे थे ? आजादी के 78 साल बाद भी हम देश को जातियों से मुक्त न कर सके ? सुप्रीमकोर्ट चीफ जस्टिस की यह चिंता भारतीय राजनेताओं की गाल पर मारा गया करारा तमाचा है। क्या हम भारत को गोरे और काले के बीच बंटा अमेरिका बनाना चाहते हैं ? सुप्रीमकोर्ट का यह दूसरा बहुत बड़ा तमाचा था। यूजीसी का नया नियम भारतीय समाज और लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है , यह सोचा किसी ने ? सीजेआई का यह तीसरा सवाल था।

सवर्णो की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर सुप्रीम अदालत ने सरकार और यूजीसी दोनों को नोटिस जारी किए हैं। करीब डेढ़ महीने बाद सुप्रीमकोर्ट इस मामले को सुनेगा। यह तय हुआ कि 2026 लगते ही आनन फानन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियम बनाए , देश ने दु:ख भोगा , सरकार को जवाब देते न बना , टीवी पर्दे से बीजेपी प्रवक्ता गायब हो गए।

निश्चित रूप से इसके लिए चेयरमैन विनीत जोशी तथा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। सीजेआई न्यायपालिका ने दिखा दिया कि वह सचमुच सबसे चिंतनशील है। विष्णु शंकर जैन तथा अन्य वकीलों का प्रयास सराहनीय है। नेता अपनी नाकामयाबी का बदला क्या इस तरह लिया जाएगा ? गौर से ढूंढिए , कोई जयचंद देश के भीतर छिपा है अथवा राजनीति के भीतर ! हर तरह से हताश हो चुके विपक्ष भी सवर्णो के साथ खड़ा मिला, अखिलेश यादव, मायावती बर्क ओवैसी इत्यादि ने यूजीसी के रेगुलेशन को गलत ठहराया। तो किसने इस रेगुलेशन के माध्यम से यह खेल खेला है ? जो भी हो पता तो चल ही जाएगा।

कोई तो है जो सरकार की लगातार लोकप्रियता से घबराया हुआ है, पर्दा उठाइए , यह बेहद जरूरी है ? सवर्णो और मुख्य न्यायधीश सूर्यकान्त पर कुछ अभद्र टिप्पणियों के स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक झटके में ही हिंदू हृदय सम्राट को उनकी जाति से बुलाया जाने लगा। तो क्या सवर्णों के लिए अभद्र टिप्पणियों की शुरुआत आज ही हुई है ? क्या इस देश में पिछले पंद्रह बीस सालों से सवर्णों के लिए भद्दी से भद्दी भाषा प्रयोग करने का चलन नहीं बन गया है ? मनु के लिए ही आज तक क्या क्या कहा गया है और किसने किसने कहा है, क्या यह बताने की आवश्कता है ? छह महीने पूर्व तक जो लोग तुलसीदास तक को गाली दे और दिलवा रहे थे, वे अब एक फर्जी स्क्रीनशॉट पर नैतिकता ढूंढने लगे ? अभी भी जो चार स्क्रीन शॉट घूम रहे हैं उनमें सब फर्जी आईडी के हैं।

प्रधानमंत्री को सबसे अधिक सम्मान सवर्ण ही देते आए हैं, और इसके कारण गालियां भी सुनते रहे हैं। आप आज भी सोशल मीडिया में देखिए, सवर्णों का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने समाज के विरुद्ध जा कर उनके साथ खड़ा है, उनके ऊपर पूरा भरोसा बनाए हुए है। यह छोटी बात है क्या ! आप कह रहे हैं कि हिन्दू एकता की बात कहां चली गई। मतलब आप चाहते हैं कि ओबीसी के रास्ते घुस कर मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई भी सवर्णों को ब्लैकमेल करें, उन्हें परेशान करें और सवर्ण इसे सर झुका कर स्वीकार करें तो हिन्दू एकता आयेगी ? मतलब आप अत्याचार और आरक्षण के लिए सवर्णों की बलि चाहते हैं और बात हिंदू एकता की करेंगे।

अपनी समस्या हमें बतायें

आपके साथ या आपके आस-पास कोई घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, जुर्म हुआ है या उत्पीड़न हुआ है अथवा आपके क्षेत्र की समस्या है और आपकी समस्या जायज है तो आपकी समस्याओ के समाधान हेतु सम्बन्धित उच्च अधिकारियों एवं शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के लिये बी पी एस न्यूज आपके साथ है। आपकी खबर शत् प्रतिशत प्रकाशित की जायेगी। एवं आपका नाम व नम्बर आपके अनुसार प्रकाशित या पूर्णतया गुप्त रखा जायेगा।

दिये गये नम्बर पर काल करें या हमें ई मेल करें।

फोन नं.- 8423454502,
bps.knp786@gmail.com

आवश्यक सूचना

प्रिय ग्राहकों/विज्ञापनदाताओ को सूचित किया जाता है कि बीपीएस न्यूज समाचार पत्र में नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। कृपया चेक/डी.डी. बी पी एस न्यूज के नाम से ही चेक आदि भेजें। नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। नगद भुगतान करने पर विज्ञापनदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- संपादक

आवश्यकता है

बी पी एस न्यूज राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र व ऑनलाइन न्यूज चैनल (पोर्टल) के लिये समस्त तहसीलों एवं ब्लाक स्तर पर ब्यूरो चीफ, संवाददाताओं, छायाकार तथा विज्ञापन प्रतिनिधियों युवक-युवतियों की आवश्यकता है।

संपर्क करें -:मो.: 8423454502
email:bps.knp786@gmail.com

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रांगण में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रांगण में ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया तथा मिष्ठान भेंट कर उनका अभिनंदन किया। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि गणतंत्र का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्राप्त है। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति से लेकर आज तक कानपुर ने इतिहास के पन्नों में अपना गौरवपूर्ण स्थान बनाया है और आधुनिक युग में भी अपनी विशिष्ट पहचान कायम रखी है। गणतंत्र सभी के लिए है और इसकी भावना को आत्मसात करना हम सबका कर्तव्य है।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने, पद की गरिमा बनाए रखते हुए न्यायपूर्ण कार्य करने तथा किसी भी व्यक्ति या समुदाय के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना फरियादियों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए शिक्षा, आपसी भाईचारा एवं सामाजिक समरसता अत्यंत आवश्यक है। भाषा, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही स्वच्छता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अपने मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखना भी हम सभी की जिम्मेदारी है।कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिनमें धर्म कुमार सिंह (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं संरक्षक), सत्येन्द्र कुमार सिन्हा (नगर अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रीय कार्यसमिति), हरीराम गुप्ता (राष्ट्रीय समन्वयक), राम कुमार सिंह स्वतंत्र (उपाध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रीय कार्यसमिति), जोगिन्दर सिंह बाजवा (महामंत्री एवं सदस्य राष्ट्रीय कार्यसमिति), एडवोकेट मृगांक शेखर आनंद, चन्द्रभान सिंह गौर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। इस अवसर पर समस्त अपर जिलाधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट सहित कलेक्ट्रेट परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

55 यू पी बटालियन एन सी सी के सिविल लाईन मुख्यालय मे मनाया गया 77वाँ गणतन्त्र दिवस

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। सूबेदार मेजर राम कुमार के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को एन सी सी यूवा कैडेट्स और एलुमेनी डॉक्टर परवेजअख्तर एलुमेनी, मीनाक्षी सिंह एलुमेनी, लखन कुमार शुक्ला व सैन्य अधिकारियों ने शस्त्र सलामी दी और राष्ट्रगान की धुन पर राष्ट्रगान गाया

।इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी अनवार अहमद को विशेष सेवा के लिए स्वतंत्रता के 77 वीं वर्षगांठ पर सेवा मेडल दे

कर सम्मानीत किया गया। 17 यू पी गर्ल्स बटालियन एन सी सी के कर्मवीर सूबेदार मेजर देवेन्द्र लाल को सैन्य सेवा, एन सी सी सेवा मे कुशल नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं उनकी सेवाओ के लिए रक्षामंत्रालय द्वारा प्रमोशन दिया गया ।

देवेन्द्र लाल को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नीरज नथानी और एडीएम ऑफिसर मेजर इंदू मिश्रा ने रैंक लगा कर लेफ्टिनेंट देवेन्द्र लाल को बधाई दी।

इस अवसर पर मुख्य रूप से सूबेदार इलियास साहब एलुमेनी, डॉक्टर परवेज अख्तर एलुमेनी, लखन कुमार शुक्ला व एलुमेनी मीनाक्षी सिंह रहे।

गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन कानपुर नगर में भव्य समारोह का किया गया आयोजन

कानपुर। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के पावन अवसर पर पुलिस लाइन कमिश्नरेट कानपुर नगर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा परेड का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।समारोह के अंतर्गत पुलिस कर्मियों द्वारा साइबर अपराध एवं अन्य सामाजिक विषयों पर जन-जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही, स्कूली बच्चों की खेलकूद गतिविधियों एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को ऊर्जा, अनुशासन एवं राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर कर दिया।

कानपुर प्रेस क्लब में मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवीन मार्केट स्थित कानपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों ने 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया। कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस बाजपेई व महामंत्री शैलेश अवस्थी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सभी उपस्थित पत्रकारों ने एक साथ राष्ट्रगीत गाते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। मंत्री शिवराज साहू ने सभी पत्रकार साथियों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया।

बीपीएस न्यूज संपादक को कैलेंडर देकर सम्मानित करते आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के अध्यक्ष एस. के. वर्मा, महासचिव राघवेंद्र सिंह एवं संयुक्त सचिव शरद प्रकाश अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य मोहन लाल मुकेश पदाधिकारियों द्वारा आयकर विभाग तथा संघ का नववर्ष 2026 कलेंडर बीपीएस न्यूज के संपादक बी.पी. साहू जी को प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया।

77वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने किया ध्वजारोहण

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी द्वारा कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा, कर्तव्यपरायणता तथा देश सेवा की शपथ दिलाई गई।कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ, जहाँ राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य भावना का अद्भुत उत्साह देखने को मिला। ध्वज के सामने सभी ने अपने संविधान, अपने देश और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सदैव समर्पित रहने का संकल्प लिया।

मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है मैं अपने धर्म के रास्ते चलूंगा, बोलकर युवक ने किया सुसाइड

» बीपीएस न्यूज/अनुज तिवारी

कानपुर। मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है मैं अपने धर्म के रस्ते चलूंगाज्पूरे देश में इस तरह का काम हो रहा है। बोलकर पनकी रतनपुर में युवक ने गुरुवार सुसाइड कर लिया। हालांकि पहले परिजनों ने अंधविश्वास के चलते सुसाइड करने की बात कही थी लेकिन युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अब धर्म परिवर्तन की चर्चाएं होने लगी हैं।

परिजनों ने शव सड़क पर रखकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया।

रतनपुर निवासी रोहित सिंह ने गुरुवार को फंदा लगाकर जान दे दी थी। परिजनों ने बताया था कि युवक की पिछले एक सप्ताह से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह मकान बेंच कर कहीं और रहने की बात कर रहा था।

वहीं घटना के दूसरे दिन मृतक युवक का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वो बोल रहा है कि मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है मैं अपने धर्म के रस्ते चलूंगाज्पूरे देश में इस तरह का काम हो रहा है। युवक जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।

मृतक की बहन निशा सिंह ने बताया कि भाई रोहित 26 जनवरी को छोटी बहन के घर लखनऊ गया था तब उन्नाव से लखनऊ के चार बाग तक काल रिसीव नहीं हुई थी।

बहन के घर पहुंच कर उसने रोते हुए जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात बताई थी।

उसने बताया था कि चार लोग ट्रेन में मिले थे जिन्होंने उसके साथ मारपीट की और चार बाग में एक मजार पर भी ले गए थे।

परिजनों ने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद परिजनों ने शव को घर के पास चौराहे पर रखकर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराने के प्रयास में जुटी है। पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि युवक का वीडियो सामने आया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत जन जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना

» प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आम जनमानस से वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा माह 01 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 तक) को जीरो फैटेलिटी माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर में सड़क सुरक्षा नियमों एवं सड़क पर सुरक्षित यात्रा के प्रति जनपदवासियों को जागरूक करने हेतु जन जागरूकता बाइक रैली एवं प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस अवसर पर आम जनमानस को दोपहिया वाहन चलाते समय चालक एवं पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने, दोपहिया वाहन चालकों को छोड़कर अन्य समस्त वाहन चालकों तथा उनमें बैठे यात्रियों/व्यक्तियों द्वारा सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही दोपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, रांग साइड एवं तेज गति से वाहन न चलाने के संबंध में जागरूक किया गया तथा यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई।

इसके अतिरिक्त प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने, ड्रंकन ड्राइविंग, अनधिकृत रूप से संचालित बसों सहित अन्य अभियोगों में नियमानुसार कार्यवाही की गई।

आंगनबाड़ी भर्ती के नाम पर अवैध वसूली से रहें सावधान

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रीति सिन्हा ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि वर्तमान में जनपद कानपुर नगर में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। इस संबंध में संज्ञान में आया है कि कुछ गैर-शासकीय एवं शरारती तत्वों द्वारा आंगनबाड़ी भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों से अवैध धनराशि की मांग कर दबाव बनाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः अनुचित एवं दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

अतः सर्वसाधारण से अपेक्षा की जाती है कि यदि आंगनबाड़ी भर्ती के संबंध में कोई भी व्यक्ति संपर्क कर किसी भी प्रकार की धनराशि अथवा अवैध लाभ की मांग करता है, तो इसकी सूचना तत्काल कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर नगर, कक्ष संख्या-15, प्रथम तल, विकास भवन, कानपुर नगर में उपलब्ध कराएं।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है तथा पोर्टल के माध्यम से जनरेट की गई ब्रॉडशीट के आधार पर जनपद स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। अतः किसी भी प्रकार के प्रलोभन, झांसे या अफवाहों में न आएं।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता पर लिखी कविता के लिए एसडीएम नर्वल को किया पुरस्कृत

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर

राष्ट्रीय मतदाता दिवस
मत का दान राष्ट्र सेवा है,
मत है जनता का अधिकार।
मत से लोकतंत्र की ताकत
मत ही जनता का हथियार।
सच्चे मतदाता बनकर हम
लोकतंत्र का मान बढ़ाएं।
अपना हिंदुस्तान बनाएं।
अपना हिंदुस्तान सजाएं।।
मत से बहुमत,मत से जनमत
मत,जन जन के मन का अभिमत।
मत से ही जनता समझाती
राजनीति से अपनी सहमति।।
भिन्न भिन्न मत पन्थ वर्ग सब
लोकतंत्र में एक समान।
संविधान की दृष्टि बराबर
हर मत को पूरा सम्मान।।
संविधान की पुस्तक को ही
गीता और कुरान बनायें।

मतदाता जागरूकता विषय पर लिखी गई कविता के लिए एसडीएम नर्वल एवं ईआरओ

आओ हिंदुस्तान बनायें
अपना हिंदुस्तान सजाएं।।
पहला कदम सभी मतदाता
मतसूची में पंजीकृत हों।
बालक वृद्ध पुरुष महिलाएं
जो जैसे हों वर्गीकृत हों।
ना छूटा हो नाम किसी का
ना ही अंकित हो दो बार।
जिसकी भी हो उम्र अठारह
मत के लिये रहे तैयार।।
सूची रहे शुद्ध शत प्रतिशत
इसकी ऐसी शान बनाएं।
आओ हिंदुस्तान बनाएं
अपना हिंदुस्तान सजाएं।
अगला कदम सभी मतदाता
घर से निकलें,मत को डालें।
मत के दिवस बिना मत डाले
और न कोई काम संभालें।
बिना लोभ लालच के भय के

महराजपुर विवेक कुमार मिश्रा को भारत निर्वाचन आयोग ने पुरस्कृत किया है। चयनित कविता के लिए उन्हें 3,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा चयनित यह कविता आयोग की आधिकारिक पत्रिका उमंग में प्रकाशित की गई है। कविता में मताधिकार के महत्व, निष्पक्ष मतदान और संविधान आधारित लोकतांत्रिक मूल्यों को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है।

स्वच्छ और निष्पक्ष वोट हो।
जाति धर्म भाषा आधारित
नहीं कहीं पर कोई खोट हो।
मत पावन है,इसे कभी न
बिकने का सामान बनाएं।
आओ हिंदुस्तान बनाएं
अपना हिंदुस्तान सजाएं।
कांटो की संगत में रहकर
केवल शूल चुने जायेंगें।
जैसे चुनने वाले होंगें
वैसे फूल चुने जाएंगे।
पांच बरस में एक बार बस
कर्तव्यों का पालन करना।
निज हित स्वार्थ त्यागकर सारे
सच्चे जनसेवक को चुनना।।
लोकतंत्र का लक्ष्य यही है
इसको सफल महान बनाएं।
आओ हिन्दुस्तान बनाएं।
अपना हिंदुस्तान सजाएं।।

खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के विरुद्ध चलाया गया सघन चेकिंग अभियान, मानकों के उल्लंघन पर की गयी कार्यवाही

» पैकेज्ड पेयजल यूनिटों पर सख्ती, 26 का निरीक्षण, 4 के लाइसेंस निलंबित, 4 पर निलंबन की संस्तुति

इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में जनपद में संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के प्रसंस्करण यूनिटों के विरुद्ध सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा कुल 26 यूनिटों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 10 यूनिटें बंद पाई गईं। निरीक्षण के दौरान कई इकाइयों में निर्धारित मानकों के उल्लंघन की पुष्टि हुई।पाई गई कमियों के आधार पर चार केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त यूनिटों के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति करते हुए केंद्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। वहीं चार स्टेट लाइसेंस प्राप्त यूनिटों की खाद्य अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।निलंबित स्टेट खाद्य अनुज्ञप्ति से संबंधित फर्मों में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मेसर्स प्रभु कृपा एंटरप्राइजेज, यशोदा नगर स्थित के. यस. टेस्टी ड्रिंक्स एंड रिफ्रेशमेंट सॉल्यूशन, गोविंद नगर स्थित संतोषा इंडस्ट्रीज तथा हंसपुरम नौबस्ता स्थित सत्यम एंटरप्राइजेज शामिल हैं।

इसी प्रकार जिन केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त यूनिटों के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई है, उनमें उद्योगकुंज पनकी स्थित मेसर्स डैडीज एंटरप्राइजेज, इस्पात नगर पनकी स्थित मेसर्स प्रयाग पैकर्स, रूमा स्थित मेसर्स विवान एंटरप्राइजेज तथा सचेंडी स्थित मेसर्स एच.डी. ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस शामिल हैं।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी

आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही पर तीन एमओआईसी को नोटिस

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। आयुष्मान कार्ड निर्माण में अपेक्षित प्रगति न मिलने को जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान शिवराजपुर, बिल्हौर और भीतरगांव के एमओआईसी की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि आयुष्मान कार्ड जैसा जीवनरक्षक जनकल्याणकारी अभियान प्राथमिकता पर है और इसमें किसी भी स्तर की शिथिलता सीधे जवाबदेही तय करेगी।समीक्षा में सामने आया कि जनवरी माह में अब तक केवल 7,258 नए आयुष्मान कार्ड ही बनाए जा सके हैं। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान को तत्काल युद्ध स्तर पर चलाया जाए और शेष पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बिना किसी देरी के बनाए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि 3 फरवरी को पुनः समीक्षा की जाएगी और यदि प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित मानी जाए।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जनपद कानपुर नगर में अब तक कुल 8 लाख 64 हजार 21 आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 79,533 वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर इस श्रेणी में कानपुर नगर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। समीक्षा के दौरान जन आरोग्य समिति के अंतर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बजट व्यय की स्थिति भी जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। ग्वालटोली, जूही, जागेश्वर, बेनाझाबर, सर्वोदय नगर और अनवरगंज यूपीएचसी में आवंटित धनराशि का उपयोग अत्यंत सीमित पाया गया, जबकि रामबाग यूपीएचसी द्वारा प्राप्त धनराशि का समुचित उपयोग न किए जाने को गंभीर लापरवाही माना गया।

जिलाधिकारी ने सात नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा जन आरोग्य समिति के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का संतोषजनक उपयोग न किए जाने पर शासन को पत्र भेजने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह धनराशि मरीजों की सुविधाओं, उपचार व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए है और भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी, डिप्टी सीएमओ डॉ आरपी यादव सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।

आईआईए भवन में 260 से अधिक खाद्य उद्योग के कर्मियों को दिया गया निःशुल्क प्रशिक्षण

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं यू0पी0 बिस्कुट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश में सभी खाद्य निर्माता फर्मों के कर्मचारियों हेतु निःशुल्क संबंधित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आईआईए भवन, कानपुर में निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया 7 कार्यक्रम में 260 से अधिक खाद्य उद्योग के कर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद्य उद्योगों में कार्यरत कर्मियों को खाद्य सुरक्षा मानकों, स्वच्छता, स्वस्थ खाद्य निर्माण प्रक्रिया तथा प्रयुक्त खाद्य तेल के सुरक्षित प्रबंधन के प्रति जागरूक करना था। प्रशिक्षण सत्र के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई एवं नमकीन निर्माण से जुड़े उद्यमियों और कर्मचारियों को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि जला हुआ अथवा बार-बार उपयोग किया गया तेल खाद्य पदार्थों में प्रयोग करना मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है तथा इससे गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

कार्यक्रम में ऋष्ह योजना के अंतर्गत प्रयुक्त खाद्य तेल के संग्रहण, निस्तारण एवं वैकल्पिक उपयोग की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्रयुक्त तेल को बायोडीजल एवं अन्य औद्योगिक उपयोगों में परिवर्तित कर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ भारत अभियान को भी सशक्त किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में इसका दुबारा प्रयोग न करें ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहायक

आयुक्त खाद्य संजय प्रताप सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा केवल विभागीय दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्नश्चस्ञ्जड्डष्ट प्रशिक्षण को सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। मौके पर

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र द्विवेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार वर्मा, डॉ अजय मौर्या व चित्रसेन सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।

एस एस ऑयल ब्रदर्स की ओर से ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव एवं श्रीनिवास ने प्रयुक्त खाद्य तेल के संग्रहण की प्रक्रिया, पंजीकरण, ट्रेसेब्लिटी एवं उसके पुनः उपयोग के तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 260 से अधिक खाद्य उद्योगों में कार्यरत उद्यमियों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता किए। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई गई।

कार्यक्रम में संस्था के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य, आलोक अग्रवाल, दिनेश बरासिया, नवीन खन्ना, जसवंत सिंह, संदीप सावलानी सहित बड़ी संख्या में उद्यमियों ने भाग लिया।

कानपुरः यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में सांसदों को सौंपा गया ज्ञापन

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। यूजीसी एक्ट 2026 के अंतर्गत बनाए गए कुछ प्रावधानों को संविधान विरोधी एवं सामाजिक सौहार्द के लिए घातक बताते हुए आज कानपुर में सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा विरोध दर्ज कराया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने माननीय सांसद अकबरपुर कानपुर देवेंद्र सिंह भोले जी तथा माननीय सांसद कानपुर रमेश अवस्थी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए इन नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की।ज्ञापन में कहा गया कि यूजीसी की Equity Committee एवं Equal Opportunity Centres से जुड़े प्रावधान व्यवहार में ÷समता÷ के स्थान पर एकतरफ़ा संरचना का निर्माण कर रहे हैं,

जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ संस्थागत असमानता उत्पन्न होने की आशंका है।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि इन समितियों में सामान्य वर्ग का अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, जिससे निर्णय प्रक्रिया संतुलित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।यह ज्ञापन सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपा गया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में अजय कुमार द्विवेदी, सुधीर द्विवेदी, रजत मिश्रा आकाश ठाकुर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रतिनिधियों ने सांसदों से अपेक्षा जताई कि वे इस विषय को संसद एवं संबंधित मंचों पर उठाकर न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करेंगे।

पुणे के बारामती में विमान हादसा

डिप्टी सीएम अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत

लैंडिंग के दौरान हादसा, विमान में लगी आग, डीजीसीए/एएआईबी ने शुरू की जांच, विमान पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था

» बीपीएस न्यूज

मुंबइ। पुणे जिले में बुधवार सुबह विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब अजित पवार (66) का विमान पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था। फ्लाइट रडार के अनुसार, विमान ने मुंबई से सुबह आठ बजकर 10 मिनट पर उड़ान भरी और सुबह करीब आठ बजकर 45 मिनट पर यह रडार की पहुंच से गायब हो गया।पवार राज्य में पांच फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के प्रचार अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि विमान सुबह आठ बजकर 50 मिनट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटना के वक्त उसमें पांच लोग सवार थे। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई।उन्होंने कहा, विमान में सवार सभी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया एक सूत्र ने बताया कि पायलट ने विमान को उतारने का प्रयास करने से पहले हवाई पट्टी के पास खराब दृश्यता के बारे में बताया था।

सूत्रों के अनुसार, बॉम्बार्डियर एयरोस्पेस के लेयरजेट डिवीजन द्वारा निर्मित मध्यम आकार का बिजनेस जेट विमान लेयरजेट 45 (एलजे45) बारामती हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास करते समय रनवे से उतर गया और उसमें आग लग गई।

पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा और दो बेटे पार्थ और जय हैं। सुनेत्रा राज्यसभा सदस्य हैं। हाल में पुणे और पिंपरी चिंचवड में हुए नगर निगम चुनाव में पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने शरद पवार की राकांपा (शप) के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था।

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह पुणे जिले में विमान दुर्घटना में पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई। उन्होंने पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री, श्री अजित पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजित पवार जी का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके परिवार, समर्थकों एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक-संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर इस दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों के परिवारों को भी इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में तीन दिन राजकीय शोक

» बीपीएस न्यूज

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर राज्य में तीन दिन के राजकीय शोक और एक दिन के अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने शोक संदेश में कहा कि अजीत पवार एक दमदार और दिलदार नेता थे। उन्होंने बहुत ही संघर्ष के बाद यह मुकाम प्राप्त किया था, अभी उन्हें महाराष्ट्र के विकास के लिए और बहुत विकास काम करने थे।मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत ही कठिन दिन है। इस तरह का नेतृत्व तैयार होने में बहुत अधिक समय लगता है। उनके निधन से महाराष्ट्र में शोक फैल गया है। अजीत पवार जमीन से जुड़े लोकनेता थे और उन्हें महाराष्ट्र की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी थी। किसी भी परिस्थिति का बिना डगमगाए सामना करने की क्षमता उनमें थी। अजीत पवार का निधन महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसे जल्द भरा जाना मुश्किल है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उन्होंने अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और सांसद सुप्रिया सुले से बात की है। अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बारे में पवार परिवार जिस तरह का निर्णय लेगा, उसकी जानकारी मीडिया को दी जाएगी।

विमान हादसे में अजित पवार की मृत्यु से स्तब्ध हूं- प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की असामयिक मृत्यु से बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अजित पवार आम लोगों के नेता थे और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ काफी मजबूत थी।अधिकारियों के अनुसार, बुधवार सुबह पुणे जिले में विमान हादसे में पवार (66) समेत पांच लोगों की मृत्यु हो गई।यह हादसा उस समय हुआ, जब विमान जिले के बारामती क्षेत्र में उतर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अजित पवार जननेता थे और उनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र की जनता की सेवा में वह हमेशा समर्पित रहे और एक परिश्रमी नेता के रूप में उनका व्यापक सम्मान था।

विकास में उनके विशेष योगदान के लिए याद किया जाएगा:राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु पर बुधवार को शोक जताते हुए कहा कि उनका असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि पवार को महाराष्ट्र के विकास खासकर सहकारी क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

अजित पवार के निधन पर ममता बनर्जी ने शोक जताया, जांच की मांग की

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। बनर्जी ने घटना की उचित जांच की भी मांग की। बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अजित पवार के अकास्मिक निधन से स्तब्ध हूं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री तथा उनके साथ सवार अन्य लोगों की आज सुबह बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में मृत्यु हो गई। इस घटना से गहरे शोक में हूं। उनके परिवार, उनके चाचा शरद पवार जी सहित, तथा दिवंगत अजित के सभी मित्रों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उन्होंने कहा, इस घटना की उचित जांच होनी चाहिए।

भारत के अंदर हुए विमान या हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुए बड़े लोग।

- » 1.अजित पवार 28 जनवरी 2026 में विमान दुर्घटना में निधन
- » 2.विजय रुपाणी 12 जून 2025 के विमान हादसे में मृत्यु
- » 3.दॉर्जी खांडू 30 अप्रैल 2011 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना
- » 4.माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 में विमान क्रैश
- » 5.संजय गांधी 23 जून 1980 में विमान दुर्घटना
- » 6.जी.एम.सी. बलयोजी 3 मार्च 2002 में हेलीकॉप्टर क्रैश
- » 7.ओ.पी. जिन्दल (राज्य मंत्री) 31 मार्च 2005 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना
- » 8.डेरा नाटुंग मई 2001 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना
- » 9.गुरनाम सिंह 1973 में विमान दुर्घटना (पूर्व पंजाब सीएम)
- » 10.बालवनत्राई मेहता 1965 में विमान दुर्घटना में मृत्यु

बिहार में सीवान, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बल अलर्ट

» भागलपुर सिविल कोर्ट में भी मिली धमकी, सीवान सिविल कोर्ट में भी धमकी

» बीपीएस न्यूज

पटना। बिहार के सीवान, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिला अदालतों को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। धमकी के बाद कोर्ट प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया।

मुजफ्फरपुर जिला सिविल कोर्ट में प्राप्त ई-मेल में सिलसिलेवार बम धमाके और आत्मघाती हमलावर के जरिए हमला करने की बात कही गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला जज ने तत्काल प्रभाव से कोर्ट परिसर खाली कराने का निर्देश जारी किया। न्यायालय कर्मियों, वकीलों और आम जनता को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बम निरोधक दस्ते (बीआरडीएस) और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया है, जो पुलिस परिसर की चप्पे-चप्पे तलाशी ले रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल की टीम जांच में जुटी है। फिलहाल पूरे कोर्ट परिसर को एक

किले की तरह सख्त सुरक्षा व्यवस्था में बदल दिया गया है। जिला प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

सीवान सिविल कोर्ट को भी बम धमाके की धमकी ई-मेल के जरिए मिली। बार काउंसिल के सचिव नवेंदु शेखर दीपक को यह ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि बुधवार दोपहर 12 बजे कोर्ट को उड़ाने की योजना है। इसके बाद कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। वकीलों और कर्मचारियों की गाड़ियों की जांच की जा रही है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शंभु दत्त शुक्ला ने कहा कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा जांच की जा रही है और कर्मचारियों तथा वकीलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

भागलपुर सिविल कोर्ट को भी बम धमाके की धमकी ई-मेल के जरिए दी गई। प्रशासनिक प्रभारी ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसपी नवगछिया को सूचना दी। एंटी बम स्क्वॉड और एंटी-सैबोटेज टीम से पूरे परिसर की जांच करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं, जबकि साइबर सेल धमकी भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है।फिलहाल, अदालतों में कामकाज जांच पूरी होने और सुरक्षा सुनिश्चित होने तक रोका गया है।

कोलकाता के गोदाम में लगी आग में 16 लोगों की मौत, 13 लापता, बचाव अभियान जारी

» बीपीएस न्यूज

कोलकाता। कोलकाता के आनंदपुर इलाके में एक गोदाम में लगी आग से कम से कम 16 जले हुए शव बरामद किए गए हैं। अधिकारी अभी भी लापता कम से कम 13 लोगों की तलाश जारी रखे हुए हैं। इस आपदा के बाद आपातकालीन सेवाओं द्वारा बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू किया गया है। अधिकारियों ने शवों की पहचान करने और त्रासदी से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के प्रयासों की पुष्टि की है। तड़के गोदाम में आग लग गई, जो वहां बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री रखे होने के कारण तेजी से फैल गई। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर पुलिस जिले के पुलिस सूत्रों के अनुसार, इमारत के अंदर अभी भी जली हुई हड्डियों के टुकड़े मौजूद हैं, जो तबाही की भयावहता को दर्शाते हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, गोदाम में सूखा खाद्य पदार्थ रखा जाता था। सोमवार तड़के करीब 3 बजे आग लगी और पैकेटबंद सूखे खाद्य पदार्थों और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों जैसी ज्वलनशील सामग्री के भंडारण के कारण तेजी से फैल गई। घटना के बाद मंत्री अरूप बिस्वास, सांसद सैनी घोष और सुजीत बोस ने घटनास्थल का दौरा किया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मैं आज यहां आया हूं। यह एक बेहद दुखद घटना है। कई लोगों की जान चली गई है। आग बहुत भीषण थी। दमकल विभाग और पुलिस आग लगने के कारणों और स्रोत की जांच कर रहे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि पहचान स्थापित करने के लिए फोरेंसिक टीमों ने बरामद शवों की जांच शुरू कर दी है। पहचान में अभी भी चुनौतियां हैं, इसलिए गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और अधिकारी परिजनों के रक्त नमूनों से डीएनए परीक्षण कराने की तैयारी कर रहे हैं। अदालत की मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। मेयर फिरहाद हकीम ने पुष्टि करते हुए कहा, ÷मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।÷ उन्होंने यह भी बताया कि डीएनए परीक्षण के माध्यम से पहचान की पुष्टि होने के बाद मुआवजा वितरित किया जाएगा।

» शंकराचार्य के साथ जो हुआ वह अनिष्टकारी घटना

भाजपा ने अनादि काल से तोड़ी है सनातनी परंपरा : अखिलेश

» बीपीएस न्यूज

लखनऊ। सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के दंभ ने अनादिकाल से चली आ रही सनातनी परंपरा को तोड़ दिया है। जगद्गुरु शंकराचार्य का तीर्थराज प्रयाग की धरती पर माघ मेले को बिना पवित्र स्नान किये छोड़कर जाना अत्यंत अनिष्टकारी घटना है। संपूर्ण विश्व का सनातन समाज इससे आहत ही नहीं बल्कि अनिश्चित भय से आशंकित है।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा और उसके संगी-साथी चाहते तो सत्ता की हनक और अपने अंहकार को त्यागकर अपने कंधों पर उनकी पालकी उठाकर, उन्हें त्रिवेणी-संगम पर पावन स्नान कराकर, उनके मर्माहत सम्मान का मान रख सकते थे।

भाजपाइयों को भ्रष्ट साधनों से अर्जित अपनी शक्ति का घमंड है, जो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है।

संतों का मन दुखी करके कोई सुख नहीं पा सकता है। भूल करने से बड़ी गलती क्षमा नहीं मांगना है। कोई भी राजनीतिक पद संतों के मान से बड़ा नहीं हो सकता। भाजपा सनातन की भी सगी नहीं है। आज हर सनातनी मन से बेहद दुखी है। धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवधान उत्पन्न करने वालों को क्या कहते हैं, ये भाजपाइयों को समझाने की जरूरत है। हमारे महाकाव्यों का यही मूलभूत संदेश है कि घमंड के दंड से कभी कोई दुर्जन नहीं बचता है। आहत संत अर्थात सत्ता का अंत।

सरकार का बड़ा ऐलान: अब महिलाओं के खाते में आएंगे 2 लाख रुपये

बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार की महिलाओं को एक सुखद समाचार दी है। जी हां, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर नीतीश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने बताया स्वच्छ के तहत योजना की लाभुक महिलाओं को अब आगे की बड़ी किश्त देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा 'इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सकें। योजना के पहले चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की राशि दी गई थी। अब आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार बहुत जल्द 2 लाख रुपये जारी किए जाएंगे।'बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शेष आवेदकों को भी नियमानुसार डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी।

इस योजना में महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद आकलन करते हुए जरूरत के हिसाब से 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान गया है।मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा 'मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कार्य प्रारंभ कर दी गई है।

यह राशि चरणों में दी जाएगी, बशर्ते कि पूर्व में दी गई राशि का रोजगार के लिए सदुपयोग किया गया हो। अच्छा रोजगार चलने की स्थिति में आवश्यकतानुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकेगी।'मुख्यमंत्री ने एक्स पर आगे लिखा 'विभाग को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनान्तर्गत लाभुकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मार्केटिंग की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही इन लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों से भी जोड़ा जाए। जैसे- पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केन्द्र, दीदी की रसोई इत्यादि।बिहार सरकार का मानना है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, बल्कि राज्य के अंदर ही उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा रोजगार के लिए मजबूरी में लोगों को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार के अनुसार अब तक 1 करोड़ 56 लाख लाभुकों के खाते में डीबीटी के जरिए राशि अंतरित कर दी गई है।

नाभि में अलग-अलग तरह के तेल लगाने से कौन सी समस्याएं होती हैं हल

नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट होता है। यह शरीर के बहुत जरूरी और सेंसिटिव हिस्सों में से एक होती है। क्योंकि नाभि में आकर शरीर की कई नसें मिलती हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में नाभि को साफ रखने से लेकर इसकी केयर करने तक के बारे में हर चीज विस्तार से बताई गई है। क्या आप जानते हैं कि नाभि में अलग-अलग तरह के तेल लगाने से आपकी कौन-कौन सी समस्याएं हल हो सकती हैं।बता दें कि नाभि में तेल लगाने के बाद छोड़ना नहीं होता है। बल्कि हल्के हाथों से मसाज भी करना होता है। इससे आपको फायदा मिलता है।

ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाभि में कौन–कौन से तेल लगाने से किन–किस समस्याओं से निजात मिलती है।

नीम का तेल

आयुर्वेद में कई सारी बीमारियों को दूर करने में नीम का महत्वपूर्ण स्थान है। नाभि में नीम का तेल लगा सकते हैं। नीम के तेल में विटामिन ई, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। साथ ही नीम के तेल में एंटी–इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। इसको नाभि में लगाने से स्किन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं।

बादाम का तेल

आपने भी बादाम तेल के काफी फायदे सुने होंगे। खासतौर पर बादाम का तेल बालों और स्किन के लिए फायदेमंद होता है।

इसमें विटामिन ई के अलावा विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन, फैटी एसिड और जिंक भी पाया जाता है। ऐसे में आप बादाम तेल को अपनी नाभि पर लगाएं। इससे स्किन और बालों से जुड़ी समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती हैं।

नारियल का तेल

कई मायनों में नारियल तेल फायदेमंद माना जाता है। इसको बालों और स्किन पर भी लगाया जाता है। नारियल तेल में विटामिन ई, विटामिन ए और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसे में नाभि पर नारियल तेल लगाने से आपकी स्किन में निखार आता है और स्किन खूबसूरत बनती है।

तिल का तेल

तिल के तेल की तासीर गर्म होती है। ऐसे में आप सर्दियों में अपनी नाभि में तिल का तेल भी लगा सकते हैं। नाभि में तिल का तेल लगाने से शरीर को गर्माहट मिलती है और इससे आपके बालों को भी मजबूती मिलती है।

सरसों का तेल

आप सभी ने सरसों के तेल के खूब फायदे सुने होंगे।

इसको खाने में खूब इस्तेमाल किया जाता है।

जब आप नाभि पर सरसों का तेल लगाते हैं, तो यह आपकी स्किन और बालों को हेल्दी बनाता है। सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है, ऐसे में इसको लगाने से आपके शरीर में गर्माहट बनी रहती है।

ब्यूटी आइकन मेगा मॉडल वैशाली भाऊरजार को मिला 'राष्ट्रीय रत्न सम्मान' अवार्ड

पिछले दिनों गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉ कृष्णा चौहान द्वारा मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 समारोह के दौरान ब्यूटी आइकन मेगा मॉडल वैशाली भाऊरजार को, कॉमेडियन सुनील पाल,अभिनेता रमेश गोयल,अली खान,सिंगर दीपा नारायण झा और एसीपी संजय पाटिल की उपस्थिति में अवार्ड दे कर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व इसके पूर्व वैशाली भाऊरजार को सुपर ह्यूमन एक्सीलेंस अवॉर्ड 2024 और अखंड भारत गौरव अवॉर्ड 2024 (मुंबई ग्लोबल) भी बॉलीवुड के विख्यात सिंगर पद्मश्री उदित नारायण के कर-कमलों से प्राप्त हो चुके हैं। मेगामॉडल वैशाली भाऊरज़ार को महात्मा गांधी रतन अवॉर्ड 2025 मिस इंडिया विनर, बॉलीवुड लीजेंड फिल्म फेस्टिवल 2025 और मुंबई ग्लोबल की ओर से अखंड भारत गौरव सम्मान 2025 जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाज़ा जा चुका है।

लगातार मिल रहे ये राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार इस बात को दर्शाते हैं कि वैशाली आज न केवल फैशन इंडस्ट्री की सशक्त आवाज़ हैं, बल्कि देश की प्रेरणास्रोत व्यक्तित्वों में से एक बन चुकी हैं। फैशन और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें बॉलीवुड आइकॉनिक अवॉर्ड 2025 से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह अवॉर्ड उन्हें निर्माता, निर्देशक और अभिनेता डॉ. धीरज कुमार के हाथों बेस्ट सुपर मॉडल के रूप में प्रदान किया गया था।

यह उनके करियर का एक और सुनहरा अध्याय बना। वर्ष 2025 के वैलेंटाइन डे के अवसर पर उन्होंने एक सामाजिक पहल करते हुए यह दिन सुरक्षा हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन (ह्वह्व) की टीम और बच्चों के साथ मनाया था। उन्होंने इस मौके पर बच्चों के साथ समय बिताकर समाज सेवा का संदेश दिया था कि विशेष दिन केवल उत्सव के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए भी होते हैं।

वैशाली वर्तमान समय में कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनकी लोकप्रियता राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई है।

वैशाली को नेहरू युवा केन्द्र, मुंबई द्वारा महाराष्ट्र युथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय सम्मान चिन्ह भी प्रदान किया जा चुका है,

जो उनके युवाओं के बीच प्रभाव और सामाजिक योगदान को मान्यता देता है। विदित हो कि वैशाली बीएसएनएल सहित कई अन्य छोटे–बड़े विज्ञापन अभियानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। एक विशेष अवसर पर जब मुंबई में 38 डिग्री तापमान में आईपीएल क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था, तब उन्होंने वहाँ पहुँचकर खिलाड़ियों का मनबल बढ़ाया था और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया था।

वैशाली का मॉडलिंग करियर जितना ग्लैमरस है, उतना ही प्रेरणादायक भी है। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई की मूल निवासी वैशाली भाऊरज़ार की मॉडल बनने की कहानी काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। वैशाली प्रारंभ में एयर होस्टेस बनना चाहती थी और वह बनी भी।

किंगफिशर एयरलाइंस के साथ उन्होंने एक्स कैबिन क्रू (एयरहोस्टेस) के रूप में काम भी किया मगर उनकी किस्मत ने उन्हें मॉडलिंग की दुनिया मे ला दिया। अपनी मेहनत, आत्मबल और कला कौशल के बल पर वैशाली भाऊरज़ार ने फैशन और समाज सेवा दोनों क्षेत्रों में स्थायी और प्रभावशाली पहचान बनाई है।

फिलवक्त वैशाली एक सफल मॉडल के रूप में युवाओं की प्रेरणा श्रोत बन चुकी हैं। आज के दौर में ब्यूटी

आइकन मेगा मॉडल वैशाली भाऊरजार का नाम उन चुनिंदा नामों में शामिल हैं, जो सौंदर्य, संवेदना और सफलता ङ्क इन तीनों को संतुलित रूप से साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं।

प्रस्तुतिः काली दास पाण्डेय

बढ़ाएं अपनी इम्यूनिटी, सर्दी-जुकाम और अन्य बड़ी बीमारियां रहेंगी दूर

पहले के समय में लोग कम बीमार पड़ते थे और शरीर में ताकत होती थी। उन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत रहती थी और मानसिक रूप से भी लोग अधिक हेल्दी नजर आते थे। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। कम उम्र से ही लोगों को बीपी, पेट की बीमारी, डायबिटीज, तनाव और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं से घिरे रहते हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और स्किन संबंधी परेशानियां तेजी से बढ़ जाती हैं।

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो इन बीमारियों के होनें की सबसे बड़ी वजह हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल है। लेकिन आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के लिए सही लाइफस्टाइल फॉलो करना बेहद जरूरी है। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए आपको उन आयुर्वेदिक आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सर्दियों में पालन करने से आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं।आयुर्वेद में सुबह जागने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 04 से 04:30 बजे माना गया है। लेकिन सूर्योदय से पहले किसी भी हाल में बिस्तर छोड़ दें। नैतिक क्रियाएं करने के बाद धूप निकलने पर योग, हल्का व्यायाम और प्राणायाम आदि करना सर्दियों में बेहद फायदेमंद होता है। ऐसा करने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है।सर्दियों के मौसम में गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद में नहाने से पहले तिल या फिर सरसों के तेल से मालिश करना लाभकारी माना जाता है। इससे स्किन का रूखापन, जोड़ों के दर्द और थकान से राहत मिलती है। मालिश करने के बाद गुनगुने पानी से नहाने से शरीर तरोताजा महसूस करता है।

वहीं सुबह का नाश्ता 08 से 09 बजे के बीच करना चाहिए। सर्दियों में दूध, दलिया, घी लगी रोटी, पोहा, मूंग दाल का चीला और उपमा जैसी गर्म और पौष्टिक चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही अखरोट, बादाम और किशमिश जैसे सूखे मेवे डाइट में शामिल करना चाहिए, इससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है।

आपको दोपहर का खाना 12 से 1 बजे के बीच करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक इस समय पाचन अग्नि समय सबसे मजबूत होती है। दोपहर में घर का बना खाना खाएं। दोपहर के खाने में दाल, मौसमी सब्जियां, रोटी, चावल, घी और छाछ को शामिल करना चाहिए।

सीएचसी चौबेपुर में जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण में 10 स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से पाए गए अनुपस्थित

» बीपीएस न्यूज

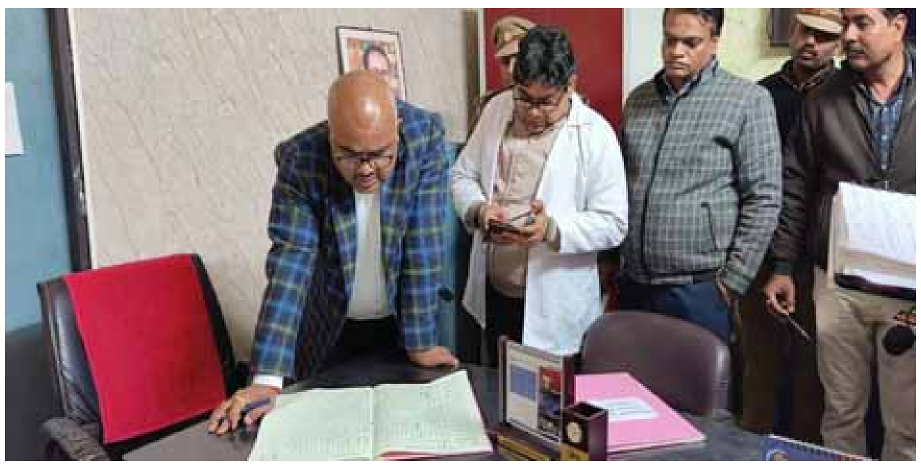

कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार अपराह्न दो बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौबेपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 10 स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी का एक दिन का वेतन काटने और स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए स्वास्थ्य कार्मिकों में द्रौपदी सावंत, अपराजिता, एकराम, नेहा साहू, मोहित पाल, अभिषेक दीक्षित, डॉ अंजना, डॉ हिमानी सचान, डॉ सुशील और डॉ विपुल शामिल हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मूवमेंट रजिस्टर का अवलोकन किया। इसमें ऑप्टिमिस्ट हिमांशु लाखा के आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए फील्ड में जाने की प्रविष्टि पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य आशा और एएनएम द्वारा ही कराया जाए तथा ऑप्टिमिस्ट से उसके पद के अनुरूप ही कार्य लिया जाए।

जिलाधिकारी ने ओपीडी रजिस्टर, दवा वितरण कक्ष और एक्स-रे कक्ष का भी निरीक्षण किया। एमओआईसी डॉ यशोवर्धन सिंह ने बताया कि शुक्रवार को ओपीडी में 170 मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। इसके अलावा सीएचसी की प्रयोगशाला में 68 मरीजों की जांच की गई। पांच मरीजों का एक्स-रे, छह दंत शल्य क्रियाएं और चार प्रसव कराए गए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीएचसी परिसर में प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई की व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मरीजों और उनके तीमारदारों से संवाद कर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की जानकारी भी ली।जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में अनुशासन, उपस्थिति और सेवा गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का चुनाव हुआ संपन्न सभी चुने हुए पदाधिकारियों ने कार्यभार किया ग्रहण

» फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के 50 वर्ष हुए पूर्ण

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की 50वीं वार्षिक आमसभा में नवनिर्वाचित पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। अध्यक्ष पद हेतु डॉ. विशाल भार्गव को चुना गया तो महासचिव पद हेतु निखिल चांडक को चुना गया। चुनाव अधिकारी डॉक्टर एम.सी. बिंदल द्वारा चुनाव संपन्न कराया गया।

अध्यक्ष, महासचिव चुनने के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा संकेत खेरिया को कोषाध्यक्ष, एन.के. गुप्ता को स्पीकर, हर्ष मिघलानी को सचिव-1, समीर भार्गव को सचिव- 2, अनूप टंडन को कानूनी सलाहकार व अजय मिश्रा को कार्यकारिणी सचिव का पद मनोनीत करते हुए सभी चुने हुए पदाधिकारी को कार्यभार ग्रहण कराया गया।

वही कार्यकारिणी समिति के पद पर अरुण भाटिया, वीरेंद्र कुमार, पवन गुप्ता, आनंद गुप्ता, गौरव अग्रवाल, डॉक्टर सौरभ भार्गव, जसकरन सिंह सागर मिश्रा एवं डॉक्टर दिवाकर तिवारी को मनोनीत किया गया।

अध्यक्ष विशाल भार्गव व महासचिव निखिल चांडक ने बताया कि फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन लगभग 50 वर्ष पुरानी प्राचीन एसोसिएशन है। इस संगठन में शहर के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी औषधि के निर्माता शामिल है। विगत 50 वर्षों से एसोसिएशन के सदस्य उच्च गुणवत्ता पूर्ण दवा निर्माण प्रक्रिया के व्यवसाय में कार्यरत हैं। एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रहा है, कि मरीजों को उच्च कोटि की दवा कम से कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सके। जिससे निम्न एवं निर्धन वर्ग भी इन औषधियों का लाभ उठाकर स्वस्थ जीवन जी सके।

VISHAL BHARGAVA
(PRESIDENT)

NIKHIL CHANDAK
(General Secretary)

सेवानिवृत्ति के दिन ही नगर निगम ने कर्मचारियों का किया पूरा भुगतान

नगर आयुक्त की पहल से 16 कर्मचारी हुए प्रफुल्लित

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। नगर निगम में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब अपने देयकों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शनिवार को नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए 16 कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया। देयकों के साथ पेंशन बुक भी कर्मचारियों को सौंप दी गई।

कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि की चेक तथा आरटीजीएस प्रक्रिया के माध्यम से उपादान, अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया। इस अवसर पर 07 सफाई कर्मचारी, 02 लिपिक, 03 बेलदार, 01 स्विचमैन, 01 भिस्ती, 01 ग्रेव डिगर तथा 01 चपरासी सेवानिवृत्त हुए। नगर आयुक्त ने कहा कि कर्मचारियों के देयकों के प्रति नगर निगम पूरी तरह सजग है। कर्मचारियों के योगदान के कारण ही नगर निगम आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहा है। जनवरी माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए समिति गठित कर यह सुनिश्चित किया गया कि सभी भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही पूरे कर दिए जाएं। अब कर्मचारियों को न तो बार-बार नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।

उन्होंने बताया कि लंबित देयकों के निस्तारण के लिए गठित समिति प्रत्येक 15 दिन में बैठक कर निर्णय लेगी। कार्यक्रम में उपादान मद में 1,49,01,900, भविष्य निधि में 56,90,358 तथा अवकाश नगदीकरण में 1,02,77,900 का भुगतान किया गया।

कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने समय पर भुगतान मिलने पर संतोष व्यक्त किया और नगर निगम प्रशासन के प्रति आभार जताया।

बजट 2026 पर वेतन भोगी वर्ग ने दी अपनी प्रतिक्रिया

कानपुर। 8वे वेतन आयोग के नोटिफिकेशन मे पेंशन को शामिल करने, वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराये मे कोरोना काल मे रोकी गए छूट को बहाल किये जाने,

18 माह का कर्मचारियों पेंशनरो के डीए एरियर का भुगतान करने पर मौन, आयकर में मानक कटौती एवं करमुक्त सीमा को यथावत बनाये रखना, संसद के प्रश्नोत्तर मे बड़ी बड़ी बाते किये की पेंशनरो का विषय वेतन आयोग मे रहेगा।

उलटे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को देने के बजाय उसे अनफडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी कहना।

मनरेगा जिसे हाल ही में विकसित भारत ग्रामीण रोज़गार गारंटी या वीबी ग्राम योजना का नाम दिया गया है, उसका भी कोई ज़िक्र न होने से छलावा नीति उजागर हो गई है।

अत: यह बजट युवा भारत एवं वेतनभागी वर्ग के लिए घोर निराशावादी है।

नौ घंटे तक नवाबगंज थाने का घेराव, कई बार पुलिस से कहासुनी

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। नवाबगंज थानाक्षेत्र के गंगानगर हाउसिंग सोसाइटी में वर्ष 2021 में हुए अधिवक्ता राजाराम वर्मा की गोली मारकर हत्या के मामले में बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी को पुलिस के उठाने के बाद सैकड़ों अधिवक्ताओं ने नवाबगंज थाने का घेराव कर जमकर हंगामा कर नारेबाजी की। नौ घंटे चले हंगामे में पुलिस के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। अधिवक्ता हर हाल में राकेश तिवारी को छोड़ने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान कई बार वकीलों की पुलिस से कहासुनी भी हुई।

बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी को बुधवार शाम 4ः30 बजे एनआरआई सिटी से उठाया गया। पुलिस और स्पेशल टीम उन्हें लेकर पूछताछ के लिए पुलिस लाइन पहुंची। इस बात की भनक लगते ही लाइन में अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस के उच्चाधिकारियों के आदेश पर पुलिस की टीमें उन्हें लेकर नवाबगंज थाने पहुंचीं। इस दौरान पीछे-पीछे सैकड़ों की संख्या में हिरासत लेने से नाराज अधिवक्ता नवाबगंज थाने पहुंचकर हंगामा कर नारेबाजी करने लगे।

हंगामा बढ़ता देख मौके पर एक प्लाटून पीएसी, काकादेव, स्वरूपनगर, कोहना, बेकनगंज, कर्नलगंज, ग्वालटोली, बजरिया, रावतपुर समेत 10 थानों के फोर्स को मौके पर बुलवा लिया गया। समय के साथ नवाबगंज थाने में अधिवक्ताओं की भी संख्या बढ़ने लगी। इस दौरान पुलिस को दोनों ओर का रास्ता बंद कर दूसरी सड़कों से वाहन सवारों को भेजना पड़ा। अधिवक्ता नवाबगंज थाने के अंदर और बाहर जमा होकर अधिवक्ता राकेश तिवारी को छोड़ने की मांग पर अड़ गए।

अधिवक्ताओं का कहना था कि पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी को राजाराम हत्याकांड में बेवजह घसीटा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब आठ बजे संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध विनोद सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने हंगामा कर रहे अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद अधिकारियों ने अधिवक्ता राकेश तिवारी से पूछताछ की। शाम साढ़े चार बजे से शुरू हुआ घटनाक्रम देर रात 12 बजे तक जारी रहा। जेसीपी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि पूछताछ की जा रही है। ये विवेचना का हिस्सा है। अधिवक्ता हैं, इसलिए उनके समर्थक थाने आ गए। हमने आरोपियों से कहा कि हमारे पास जो साक्ष्य हैं, उनका काउंटर करें। अगर वह काउंटर कर अपने साक्ष्य रख देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अगर साक्ष्यों में वह दोषी मिलेंगे तो आगे की कार्रवाई होगी। इस मामले में जो शूटर थे, उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।वर्ष 2021 में एनआरआई सिटी क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। आरोपियों को जेल भेजने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पीड़ित के बेटे ने विवेचना से असहमति जताई थी। करीब दो-तीन महीने पहले शिकायती पत्र देते हुए दोबारा विवेचना की मांग की। आदेश मिलने पर दोबारा विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान कुछ नए नाम सामने आए हैं।

एडीएम सिटी ने सदर तहसील का किया निरीक्षण

» शौचालय की सफाई और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने को कहा

» शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समय से करने का आदेश

» बीपीएस न्यूज

कानपुर ।एडीएम सिटी ने शनिवार को सदर तहसील का निरीक्षण किया। पटलों के साथ लेखपालों से कार्य संबंधी जानकारी ली। फरियादियों से बात की और शिकायत निस्तारण का आदेश दिया। गंदगी देख एडीएम सिटी ने नाजिर से पूछा नाजिर का क्या अर्थ होता है।एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि राजस्व कार्य में तेजी, फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समय से, सफाई को लेकर नगर निगम को लेटर लिखने का आदेश दिया है।एडीएम सिटी ने सदर तहसील में आने वाले फरियादियों की परेशानी सुनी और इसे जल्द निस्तारण को निर्देशित किया। इसके बाद तहसील के कार्यालयों का निरीक्षण किया। वहां मौजूद लोगों से बात की और परेशानी जानी। शौचालय की सफाई और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने को कहा है।उन्होंने तहसील के लेखपालों, संग्रह अमीनों, पटल सहायकों व नायब तहसीलदारों के साथ बैठक कर निर्देशित किया कि शिकायतों, राजस्व कार्यों, वादों और वसूली से संबंधित कार्यों को तत्परता से गुणवत्तापरक व समय से निपटाया जाए। इसके साथ ही तहसील के संग्रह अनुभाग, खतौनी सेक्शन व अन्य पटलों और न्यायालयों का एडीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम सदर अनुभव सिंह, तहसीलदार विनय द्विवेदी और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

घायल पुलिस कर्मियों के न्याय के लिए जारी है लड़ाई

पुलिस कर्मियों के न्याय के लिए जारी है कोशिश

» छह साल से लंबित पुलिस बैरक हादसा मामला, अधिकारियों की चुप्पी पर आयोग सख्त

» पुलिस लाइन बैरक हादसे में पुलिस कर्मियों के न्याय के लिए पंकज कुमार सिंह ने 6 साल पहले दाख़िल की थी एनएचआरसी में रिट

» मृतक पुलिस कर्मी की बेवा को दिलाया 25 लाख मुआवज़ा, आश्रित माँ को 5 लाख़ पर घायल पुलिस कर्मियों के न्याय के लिए जारी है लड़ाई, एनएचआरसी कोर्ट ने मुख्य सचिव को भेजा नोटिस

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। कानपुर पुलिस लाइन में हुए बैरक हादसे को छह साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक घायल पुलिसकर्मियों को मुआवज़ा नहीं मिल सका है। इस गंभीर लापरवाही पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की कोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।यह निर्देश याचिकाकर्ता कानपुर के इंजीनियर पंकज कुमार सिंह की दलीलों पर कार्रवाई करते हुए एनएचआरसी कोर्ट ने दिए।

आयोग ने अधिकारियों से छह सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा है कि हादसे में घायल तीन पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले मुआवज़े का क्या हुआ। आयोग ने यह भी पूछा है कि यदि मुआवज़ा दिया जा चुका है, तो उसके प्रमाण अब तक प्रस्तुत क्यों नहीं किए गए। यह मामला वर्ष 2020 से लंबित है। आयोग के अनुसार, हादसे में शहीद हुए सिपाही अरविंद सिंह की पत्नी नीलेश कुमार को 20 लाख और मां प्रेमश्री को 5 लाख मुआवज़ा दे दिया गया है और उसके दस्तावेज भी जमा किए जा चुके हैं, लेकिन घायलों के मामले में अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

वर्ष 2020 में कानपुर पुलिस लाइन में स्थित करीब 105 साल पुरानी बैरक की छत गिर गई थी। इस हादसे में सिपाही अरविंद सिंह की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे।इंजीनियर पंकज कुमार ने 12 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की थी। लंबे समय बाद आयोग ने मृतक के आश्रितों को मुआवज़ा देने का आदेश दिया, लेकिन घायलों के मामले में प्रशासन की उदासीनता अब भी बनी हुई है।22 जनवरी को हुई सुनवाई में आयोग ने स्पष्ट नाराज़गी जताते हुए कहा कि यदि मुआवज़ा दिया जा चुका है, तो उसके प्रमाण तुरंत पेश किए जाएँ। आयोग ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए छह सप्ताह की मोहलत दी है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आज से

» प्रयोगात्मक परीक्षा- 2 फरवरी से शुरू

» 165 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर

» कंट्रोल रूम से जिला स्तर पर निगरानी होगी

» परीक्षकों की नियुक्ति बोर्ड के निर्देशानुसार

» मुख्य परीक्षा-18 फरवरी से, 78 केंद्र तैयार

फर्रुखाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट (प्रयोगात्मक) परीक्षाएं 2 फरवरी से जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रयोगात्मक परीक्षा में कोई लापरवाही न बरतें। परिषद ने परीक्षा केंद्रों और पंजीकृत छात्रों की सूची उपलब्ध कराई है।उन्होंने कहा कि 165 परीक्षा केंद्रों में वॉइस रिकॉर्डर और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे निम्न विवरण शीघ्र जिला विद्यालय निरीक्षक को कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या, प्रयोगशाला संचालन की स्थिति, सीसीटीवी कैमरों की संख्या, डीवीआर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराएं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि परीक्षा के दूसरे चरण में दूसरे जिलों से परीक्षक बोर्ड के निर्देश पर परीक्षा लेने आएंगे। परीक्षा की निगरानी जिला कंट्रोल रूम से की जाएगी, जिसके लिए शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। कंट्रोल रूम का प्रभारी राम लखन पाल होंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा के बाद 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की मुख्य परीक्षा शुरू होगी। इस बार हाई स्कूल और इंटर के लिए 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा अवैध ठेलों को हटवाने तथा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न होने देने हेतु निर्देशित किया

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। पुलिस उपायुक्त यातायात रवीन्द्र कुमार द्वारा शहर में सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहर के प्रमुख मार्गों एवं चौराहों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपायुक्त द्वारा यातायात संचालन की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया गया तथा यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए । निरीक्षण स्थल हैलेट हॉस्पिटल मार्ग, फज़्लगंज चौराहा, बीओबी चौराहा, नन्दलाल चौराहा, चावला चौराहा, दीप तिराहा स्थल का निरीक्षण किया गया।

प्रमुख चौराहों पर बढ़ते यातायात दबाव, वाहनों की अनियंत्रित एवं अवैध पार्किंग तथा जाम की स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित यातायात अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पीक आवर्स के समय अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए तथा अवैध पार्किंग एवं अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित एवं प्रभावी प्रवर्तनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।अस्पताल मार्गों पर विशेष ध्यान देते हुए एम्बुलेंस एवं अन्य आपातकालीन वाहनों की निर्बाध एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके ।

गोविन्द नगर पुल पर अवैध रूप से लगाए जा रहे सब्जी, फल एवं अन्य ठेलों के कारण यातायात बाधित होने की स्थिति का संज्ञान लेते हुए पुलिस उपायुक्त द्वारा एसएचओ फज़्लगंज एवं एसएचओ गोविन्द नगर को तत्काल प्रभाव से ऐसे अवैध ठेलों को हटवाने तथा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न होने देने हेतु निर्देशित किया गया ।

बार काउंसिल चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा किया गया मतदान स्थल का निरीक्षण

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। बार काउंसिल चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय/अपराध) विनोद कुमार सिंह द्वारा मतदान स्थल एवं उसके आस-पास की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त (अभिसूचना) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतदान केंद्र का भ्रमण कर मतदान प्रक्रिया, मतदाताओं की सुचारु आवाजाही, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती, भीड़ प्रबंधन तथा चिन्हित संवेदनशील स्थलों की समीक्षा की।पुलिस आयुक्त द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्ण सतर्कता, निष्पक्षता एवं अनुशासन के साथ कर्तव्य निर्वहन करने तथा किसी भी आपात अथवा अप्रिय स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

जनगणना 2027 की तैयारी तेज, कानपुर में 13 हजार से अधिक कार्मिक होंगे तैनात

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जनगणना की समयसीमा, कार्ययोजना और डिजिटल प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना का प्रथम चरण 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक संचालित होगा। जनगणना का द्वितीय चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा। जनपद में जनगणना कार्य के लिए कुल 13,089 कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनगणना 2027 देश की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद की आठवीं जनगणना होगी, जो गांव, शहर और वार्ड स्तर पर प्राथमिक आंकड़ों का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय स्रोत होती है। इसके माध्यम से आवास की स्थिति, मूलभूत सुविधाएं, परिसंपत्तियां, जनसांख्यिकीय विवरण, धर्म, भाषा, साक्षरता, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियां, प्रवासन और उर्वरता जैसे विषयों पर सूक्ष्म स्तर का डेटा प्राप्त होता है।जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और पहली बार नागरिकों को स्वगणना का विकल्प दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनगणना से पूर्व 15 दिनों की अवधि में नागरिक सेंसस सेल्फ एन्युमरेशन पोर्टल एवं एप के माध्यम से स्वयं अपनी गणना कर सकेंगे। कोई भी सामान्य निवासी ऑनलाइन प्रश्नावली भरकर स्वगणना कर सकता है।घर-सूचीकरण चरण के दौरान सर्वेक्षक भवन के उपयोग, निर्माण सामग्री, कमरों की संख्या, स्वामित्व की स्थिति, जल, विद्युत और शौचालय की उपलब्धता, खाना पकाने के ईंधन के प्रकार तथा फोन, वाहन और टेलीविजन जैसी परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रकार के विवरण दर्ज करेंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण 28 फरवरी तक, फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण 31 मार्च तक और प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण हर हाल में 15 मई तक पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में लखनऊ से आए सहायक निदेशक सेंसस दिनेश यादव ने जनगणना प्रक्रिया को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी, अपर नगर आयुक्त आवेश खान, जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत सिंह, डीआईओ शांतनु श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी ईशा शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मण्डलायुक्त ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मण्डलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन ने मण्डलायुक्त कार्यालय में ध्वजारोहण किया। मण्डलायुक्त ने सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि हम सभी को अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन संविधान में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम सभी को जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना हमारा कर्तव्य है तथा अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए न्यायपूर्ण कार्य करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव–चाहे वह जाति, धर्म या मजहब के आधार पर हो–नहीं किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। भारत में 77 वर्षों से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हमारा देश विविध भाषाओं और संस्कृतियों के बावजूद ÷विविधता में एकता÷ का उत्कृष्ट उदाहरण है।

मण्डलायुक्त ने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है, जिससे सभी की भागीदारी और शक्ति समान बनी रहती है।

मण्डलायुक्त ने कहा कि देश की प्रगति के लिए शिक्षा, आपसी भाईचारा एवं सामाजिक समरसता अत्यंत आवश्यक है। हमें भाषा, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही स्वच्छता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार अपने मोहल्ले और शहर को भी स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।

उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया तथा ÷वसुधैव कुटुम्बकम्÷ के संदेश को विश्वभर में प्रसारित करने पर जोर दिया।कार्यक्रम के दौरान मण्डलायुक्त द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया, जिनमें सरोज कुमार, नरेन्द्र कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, पदमकांत गुप्ता, राजकुमारी मिश्रा, गौरव दीक्षित, अनिल कुमार शुक्ला, नीलम देवी, बीना शुक्ला, कपिल कुमार मिश्रा आदि शामिल रहे।

इस अवसर पर अपर आयुक्त बृज किशोर, अपर आयुक्त रेनू सिंह, अपर आयुक्त सुशीला, कमिश्नरी बार अध्यक्ष दिनेश वर्मा, महामंत्री अश्वनी द्विवेदी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन, अधिवक्तागण सहित मण्डलायुक्त कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

भूतल की तीन दुकानों में आग, बिल्डिंग में फंसे आठ लोगों को बचाया

कानपुर। बेकनगंज थाना क्षेत्र में घनी आबादी वाले तलाक महल लाल कुआं चौराहे पर दो मंजिला बिल्डिंग के भूतल पर स्थित तीन दुकानों में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। सूचना पर चार दमकल लेकर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान धुएं के काले गुबार के बीच बिल्डिंग में फंसे आठ लोगों को खिड़की तोड़कर सकुशल बचा लिया गया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया जा सका।

तलाक महल लाल कुआं चौराहे पर रहमानी मार्केट के बगल में मो. शमीम की दशकों पुरानी दो मंजिला बिल्डिंग है। बिल्डिंग के भूतल पर मो. जाहिद और मो. अकील की लतीफ स्वीट हाउस नाम से दुकान है। ठीक बगल में मो. दिलशाद की बिरयानी शॉप है। वहां शनिवार सुबह करीब 7~30 बजे मिठाई की दुकान से तेज धुआं उठता देख क्षेत्र के रहने वाले अयाज ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लाटूश रोड, फजलगंज और कर्नलगंज फायर स्टेशन से चार गाड़ियां पहुंचीं।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि दमकलकर्मियों ने रास्ता रुकवाकर तीनों दुकानों पर पानी डालना शुरू किया। आग की लपटें पहली मंजिल तक पहुंच गईं जहां मकान मालिक, चार किरायेदार व एक अन्य फंस थे। वहीं, बिरयानी की दुकान में सो रहे दो कर्मचारी भी धुएं से घिर गए। दमकलकर्मियों ने खिड़की तोड़कर कुलआठ लोगों का रेस्क्यू किया। करीब डेढ़ घंटे बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। सीएफओ ने कहा कि आग की घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। दुकानदारों ने अपना लाखों रुपये का नुकसान बताया है।

बीपीएस न्यूज (साप्ताहिक समाचार पत्र)
मुद्रक प्रकाशक स्वात्वाधिकारी बुद्ध प्रकाश साहू द्वारा मां प्रिन्टर्स गार्डेन नं. 6-ए/7 रेल बाजार कानपुर नगर से मुद्रित एवं 344- बगाही भट्ठा टी.पी. नगर कानपुर से प्रकाशित। आर.एन.आई. नं. UPHIN/2016/66740, डाक पंजीयन सं. कानपुर सिटी 304/2024-2026, संपादक बुद्ध प्रकाश साहू मो.: 8423454502, व्हाट्सअप 9335908846
email:bps.knp786@gmail.com, info@bpsnews.in , www.bpsnews.in नोट-समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र कानपुर नगर न्यायालय होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त लेखों एवं समाचारों की जिम्मेदारी लेखकों व संवाददाताओ की होगी। कृपया कोई भी आपत्ति हो तो 15 दिनो के अंदर भेजे।